

भारत सरकार  
पंचायती राज मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 3854  
दिनांक 12.08.2025 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहुँच और डिजिटल अवसंरचना

3854. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश की ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड और डिजिटल कनेक्टिविटी की वर्तमान स्थिति का आकलन किया है;
- (ख) यदि हाँ, तो तस्वीर व्यौरा क्या है और राज्य-वार इंटरनेट की कार्यशील सेवा और डिजिटल अवसंरचना से सुसज्जित ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है और इसका अनुपात क्या है;
- (ग) क्या ई-ग्राम स्वराज पोर्टल सभी पंचायतों में पूरी तरह से कार्यान्वित है और अन्य प्रमुख डेटाबेस के साथ एकीकृत है;
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त पोर्टल के पूरी तरह से एकीकृत होने में कितना समय लगने की संभावना है; और
- (ड) क्या सरकार ने पंचायत स्तर पर डिजिटल गवर्नेंस उपकरणों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए रखरखाव, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता हेतु संसाधन आवंटित किए हैं और यदि हाँ, तो तस्वीर व्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) और (ख) सरकार अपने डिजिटल इंडिया विज़न के एक भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को मज़बूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार, दूरसंचार विभाग (डीओटी) और संबंधित राज्य सरकारों के समन्वय से ग्राम पंचायत स्तर पर ब्रॉडबैंड और डिजिटल बुनियादी ढाँचे की वर्तमान स्थिति की नियमित निगरानी की जा रही है।

ब्रॉडबैंड पहुँच में तेज़ी लाने के लिए, दूरसंचार विभाग द्वारा भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि देश भर की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और पारंपरिक स्थानीय निकायों (टीएलबी) को हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। भारतनेट यूएनएमएस डैशबोर्ड पर दिनांक 07.08.2025 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कुल 2.69 लाख जीपी/टीएलबी में से, भारतनेट परियोजना के अंतर्गत 2.18 लाख से अधिक तैयार सेवा बिंदु (सर्विस-रेडी पॉइंट) बनाए जा चुके हैं।

इसके अलावा, डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 04.08.2023 को संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दी। इसमें भारतनेट के फेज-। और फेज-॥ के तहत मौजूदा नेटवर्क का उन्नयन और शेष अछूते ग्राम पंचायतों तक कनेक्टिविटी का विस्तार शामिल है। इस पहल के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण **अनुलग्नक-।** में दिया गया है, जबकि ज़िला-वार डेटा भारतनेट पोर्टल (<https://bbnl.nic.in>) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। पंचायतों की पहुंच को आसान बनाने के लिए, सेवा के लिए तैयार क्षेत्रों में फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) कनेक्शन के लिए आवेदन करने हेतु ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर एक इंटरफेस भी उपलब्ध कराया गया है।

इसके अतिरिक्त, पंचायती राज मंत्रालय ई-ग्रामस्वराज प्लेटफॉर्म के माध्यम से पंचायत-स्तरीय डिजिटल गतिविधियों पर निगरानी रखता है। वित्त वर्ष 2024-25 में, 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (जीपीडीपी) अपलोड की और ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस के माध्यम से ₹61,000 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, 2.46 लाख ग्राम पंचायतें पहले ही अपनी जीपीडीपी अपलोड कर चुकी हैं और लगभग 2.05 लाख ग्राम पंचायतों ने इसी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ₹19,000 करोड़ से अधिक की धनराशि के हस्तांतरण को सुगम बनाया है। ये विकास अंतिम छोर तक डिजिटल पहुंच में सुधार और जमीनी स्तर पर डिजिटल शासन को मज़बूत बनाने की दिशा में सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है।

**(ग) और (घ)** ऑनलाइन योजना, बजट, लेखांकन और भुगतान को सक्षम बनाकर पंचायत के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए देश भर की सभी ग्राम पंचायतों के लिए ई-ग्रामस्वराज पोर्टल चालू कर दिया गया है। राज्यों को पोर्टल पर डेटा प्रविष्टि सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अब तक, अधिकांश पंचायतें पंचायत के कामकाज से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए इस प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से उपयोग कर रही हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में, देश भर की कुल 2.55 लाख ग्राम पंचायतों ने अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (GPD) अपलोड की और ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफ्रेस के माध्यम से 2.53 लाख ग्राम पंचायतों (राज्यवार विवरण अनुलग्नक -॥ में दिया गया है।) ने ₹61,000 करोड़ से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की गई।

पोर्टल को अन्य प्रमुख प्लेटफार्मों के साथ भी एकीकृत किया गया है, जैसे कि वास्तविक समय के वित्तीय लेनदेन के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), खरीद के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस

(जीईएम), इंटरनेट कनेक्टिविटी ट्रैकिंग के लिए भारतनेट/बीएसएनएल और योजना लाभार्थी संबंधी जानकारी साझा करने के लिए अन्य मंत्रालयों के डेटाबेस।

मंत्रालय ई-पंचायत एमएमपी के अंतर्गत डेटा प्रविष्टि और प्लेटफॉर्म के उपयोग को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। फीडबैक के आधार पर निरंतर सुधार किए जा रहे हैं, जिनमें ई-ग्रामस्वराज में कार्यक्षमता उन्नयन और पंचायत अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण पहल शामिल हैं। सभी राज्य अपने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, ई-पंचायत एमएमपी को लागू करने के प्रयास कर रहे हैं। हालाँकि, देश भर में पंचायतों की तैयारी के स्तर में भिन्नता के कारण, राज्य इन एप्लीकेशनों के कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(ड) जी हाँ, ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के अंतर्गत, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत स्तर पर डिजिटल शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए कई पहल की हैं। हालाँकि ई-पंचायत एमएमपी के अंतर्गत राज्यों को कोई प्रत्यक्ष धनराशि प्रदान नहीं की जाती है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर सहायता के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक (एनआईसीएसआई) के माध्यम से संसाधन आवंटित किए जाते हैं। इनमें ई-ग्रामस्वराज जैसे ई-पंचायत एप्लीकेशनों के विकास, रखरखाव और संवर्धन से संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आरजीएसए के अंतर्गत, निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान की जाती है:

- ई-गवर्नेंस उपकरणों पर पंचायत पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण;
- हैंडहोल्डिंग और क्षेत्र-स्तरीय आईसीटी सहायता के लिए तकनीकी जनशक्ति;
- पंचायत कार्यालयों में आईटी अवसंरचना और इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रावधान;
- पंचायतों में डिजिटल अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं और आईईसी गतिविधियां।

इन उपायों का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को नियोजन, निगरानी, लेखांकन और समग्र शासन कार्यों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सशक्त बनाना है।

\*\*\*

अनुलग्नक-1

'ग्राम पंचायतों में इंटरनेट की सुगमता और डिजिटल अवसंरचना' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3854 जिसका उत्तर दिनांक 12.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए तैयार सेवा बिंदुओं का राज्यवार विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	तैयार सेवा बिंदुओं की संख्या *
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	70	81
2	आंध्र प्रदेश	13327	12972
3	अरुणाचल प्रदेश	2108	1145
4	असम	2665	1634
5	बिहार	8054	8860
6	छत्तीसगढ़	11623	9759
7	गोवा	191	0
8	गुजरात	14674	14563
9	हरियाणा	6225	6204
10	हिमाचल प्रदेश	3615	416
11	जम्मू और कश्मीर	4291	1115
12	झारखंड	4345	4649
13	कर्नाटक	5948	6251
14	केरल	941	1130
15	लद्दाख	193	193
16	लक्ष्मीपुर	10	9
17	मध्य प्रदेश	23011	18106
18	महाराष्ट्र	27952	24778
19	मणिपुर	3812	1485
20	मेघालय	6838	697
21	मिजोरम	843	539
22	नागालैंड	1315	236
23	ओडिशा	6794	7099
24	पुदुचेरी	108	101
25	पंजाब	13236	12807
26	राजस्थान	11193	8997
27	सिक्किम	199	54
28	तमिलनाडु	12525	10298
29	तेलंगाना	12860	10926
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	42	41
31	त्रिपुरा	1194	772
32	उत्तर प्रदेश	57691	47451
33	उत्तराखण्ड	7788	2021
34	पश्चिम बंगाल	3339	2958
	<b>कुल</b>	<b>269020</b>	<b>218347</b>

\* डेटा भारतनेट यूएनएमएस डैशबोर्ड से प्राप्त किया जाता है, और कुछ ग्राम पंचायतों में कई सेवा-तैयार बिंदु हो सकते हैं।

'ग्राम पंचायतों में इंटरनेट की सुगमता और डिजिटल अवसंरचना' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3854 जिसका उत्तर दिनांक 12.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर ई-ग्रामस्वराज को अपनाना

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्र.म पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या	शार्मिल ग्र.म पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ग्र.म पंचायतों और समकक्ष	ब्लॉक पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या	शार्मिलब्लॉक पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वालीजिला क पंचायतों	जिला पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या	शार्मिलजिला पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वालीजिला पंचायतों
1	आंध्र प्रदेश	13328	13320	13002	660	660	645	13	13	13
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	2108	426	0	0	0	27	26	11
3	असम	2662	2197	2183	191	191	191	30	29	27
4	बिहार	8054	8054	8046	534	534	531	38	38	38
5	छत्तीसगढ़	11701	11684	11540	146	146	146	33	33	27
6	गोवा	191	191	97	0	0	0	2	2	2
7	गुजरात	14656	14645	14006	248	248	248	33	33	33
8	हरियाणा	6226	6226	5980	143	143	134	22	22	22
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3615	3557	81	81	81	12	12	12
10	झारखण्ड	4345	4345	4335	264	264	263	24	24	24
11	कर्नाटक	5954	5954	5942	238	232	127	31	31	29
12	केरल	941	941	941	152	152	152	14	14	14
13	मध्य प्रदेश	23011	23011	22987	313	313	311	52	52	52
14	महाराष्ट्र	27955	27940	27025	351	351	312	34	34	34
15	मणिपुर	3812	161	125	0	0	0	12	6	4
16	मेघालय	6817	0	0	2241	0	0	3	3	0
17	मिजोरम	842	842	832	0	0	0	0	0	0
18	नगालैंड	1289	6	977	0	0	0	0	0	0

19	ओडिशा	6794	6794	6794	314	314	314	30	30	30
20	ਪੰਜਾਬ	13237	13234	10240	153	151	123	23	22	19
21	राजस्थान	11222	11219	10905	361	353	351	33	33	33
22	सिक्किम	199	199	195	0	0	0	6	6	6
23	तमில்நாடு	12525	12525	12520	388	388	388	36	36	36
24	तेलंगाना	12991	12768	12648	572	540	514	32	32	32
25	त्रिपुरा	1194	1194	1175	75	75	75	9	9	9
26	उत्तराखण्ड	7795	7795	7757	95	95	95	13	13	13
27	उत्तर प्रदेश	57691	57691	57638	826	826	819	75	75	75
28	पश्चिम बंगाल	3339	3339	3339	345	345	345	22	21	21
<b>कुल</b>		<b>264494</b>	<b>252969</b>	<b>244235</b>	<b>8691</b>	<b>6402</b>	<b>6165</b>	<b>659</b>	<b>649</b>	<b>616</b>